

EXAM GENIUS
Presents
GENIUS
CURRENT
AFFAIRS

In Bilingual
25 & 26 Jan 2026



India's No. 1 Platform for UPSC
| SSC | BANK | RAILWAY Exam

Achieve Success with Exam Genius - Your Ultimate Guide to Reasoning Mastery !



Ques : What is the minimum initial and annual contribution required under the NPS Vatsalya Scheme as per PFRDA Guidelines 2025?

PFRDA द्वारा जारी NPS वात्सल्य योजना दिशानिर्देश 2025 के अनुसार न्यूनतम प्रारंभिक एवं वार्षिक योगदान कितना है?

- A) ₹100
- B) ₹250
- C) ₹500
- D) ₹1,000
- E) ₹2,000

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) issued the NPS Vatsalya Scheme Guidelines 2025 to strengthen long-term financial security for minors.
- पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नाबालिगों की दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए NPS वात्सल्य योजना दिशानिर्देश 2025 जारी किए।
- NPS Vatsalya is a contributory savings and long-term financial security scheme designed exclusively for minors.
- NPS वात्सल्य एक योगदान आधारित बचत एवं दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा योजना है, जिसे विशेष रूप से नाबालिगों के लिए तैयार किया गया है।
- The scheme was announced in the Union Budget 2024–25 and launched on 18 September 2024 by Finance Minister Nirmala Sitharaman.
- इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024–25 में की गई थी और 18 सितंबर 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च किया गया।
- The scheme is open to all Indian citizens, including NRI/OCI, below 18 years of age.
- यह योजना 18 वर्ष से कम आयु के सभी भारतीय नागरिकों (NRI/OCI सहित) के लिए खुली है।
- The minor is the sole beneficiary; the account is opened in the minor's name and operated by the guardian.
- नाबालिग ही एकमात्र लाभार्थी होता है; खाता नाबालिग के नाम पर खुलता है और अभिभावक द्वारा संचालित होता है।





- The minimum initial and annual contribution under the scheme is ₹250, with no maximum limit.
- योजना के तहत न्यूनतम प्रारंभिक एवं वार्षिक योगदान ₹250 है और अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है।
- Contributions can also be gifted by relatives and friends.
- रिश्तेदार और मित्र भी उपहार के रूप में योगदान कर सकते हैं।
- Partial withdrawal is allowed after completion of three years from account opening.
- खाता खोलने के तीन वर्ष बाद आंशिक निकासी की अनुमति है।
- Up to 25% of own contributions (excluding returns) can be withdrawn.
- केवल स्वयं के योगदान का 25% तक (रिटर्न को छोड़कर) निकाला जा सकता है।
- Withdrawals are permitted for education, medical treatment, and specified disabilities.
- शिक्षा, चिकित्सा उपचार और निर्दिष्ट दिव्यांगता के लिए निकासी की अनुमति है।
- Partial withdrawal is allowed twice before 18 years and twice between 18–21 years, subject to conditions.
- 18 वर्ष से पहले दो बार और 18–21 वर्ष के बीच दो बार आंशिक निकासी की अनुमति दी गई है।

EXAM
Genius





Recent News Headlines Related to RBI

- RBI issued revised Priority Sector Lending guidelines to improve effective delivery of bank credit to priority sectors.
- RBI ने प्रायोरिटी सेक्टरों तक बैंक ऋण की प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संशोधित PSL दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- Karnataka Bank has secured the necessary authorization from the Reserve Bank of India (RBI) and approval from the Department of Treasuries, Government of Karnataka.
- कर्नाटक बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और कर्नाटक सरकार के ट्रेजरी विभाग से आवश्यक मंजूरी प्राप्त हुई है।
- The Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) submitted an application to the RBI under the Omnibus Framework for recognition of Self-Regulatory Organisations (SROs) for Regulated Entities.
- फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FEDAI) ने विनियमित संस्थाओं के लिए SRO की मान्यता हेतु RBI के ओम्निबस फ्रेमवर्क के तहत आवेदन किया था।
- The Reserve Bank of India (RBI) has fixed the Ways and Means Advances (WMA) limit for the Government of the National Capital Territory of Delhi (GNCTD) at ₹890 crore.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (GNCTD) सरकार के लिए Ways and Means Advances (WMA) की सीमा ₹890 करोड़ निर्धारित की है।
- Under the draft amendments issued by the RBI, a director who has completed 10 years of continuous tenure on the board of a UCB, State Co-operative Bank, or Central Co-operative Bank will be eligible for re-appointment to the same bank only after a minimum cooling-off period of three years.
- RBI द्वारा जारी मसौदा संशोधनों के अनुसार, शहरी सहकारी बैंक (UCB), राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक के बोर्ड में 10 वर्षों का निरंतर कार्यकाल पूरा करने वाला निदेशक कम से कम तीन वर्ष के कूलिंग-ऑफ पीरियड के बाद ही उसी बैंक में पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।
- PayG has secured approval from the Reserve Bank of India (RBI) to operate as a Payment Aggregator–Physical (PA-P) and Cross-Border Payment Aggregator (PA-CB).
- पे-जी (PayG) को पेमेंट एग्रीगेटर–फिजिकल (PA-P) और क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर (PA-CB) के रूप में संचालन के लिए RBI की मंजूरी मिली है।





Ques : Which institution has revamped its ATM infrastructure to make banking services more accessible and user-friendly across the country?

देशभर में बैंकिंग सेवाओं को अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने के लिए किस संस्था ने अपनी ATM अवसंरचना का नवीनीकरण किया है?

- A) Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक
- B) Department of Posts / डाक विभाग
- C) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- D) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
- E) NABARD / नाबार्ड

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- In a major step towards enhancing financial inclusion, the Department of Posts has revamped its ATM infrastructure across India.
- वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए डाक विभाग ने देशभर में अपनी ATM अवसंरचना का नवीनीकरण किया है।
- A total of 887 ATMs have been installed at various post offices, enabling citizens to access essential banking services near their homes.
- विभिन्न डाकघरों में 887 ATM स्थापित किए गए हैं, जिससे नागरिकों को अपने घर के पास ही आवश्यक बैंकिंग सेवाएँ मिल सकें।
- These ATMs allow customers to withdraw cash, check account balances, and perform other basic banking transactions conveniently.
- इन ATM के माध्यम से ग्राहक नकद निकासी, खाता शेष जांच और अन्य बुनियादी बैंकिंग लेन-देन आसानी से कर सकते हैं।
- The initiative strengthens the role of post offices as important centers for last-mile banking services in rural and urban areas.
- यह पहल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लास्ट-माइल बैंकिंग सेवाओं के रूप में डाकघरों की भूमिका को मजबूत करती है।





Ques: Why has the Reserve Bank of India (RBI) proposed reopening the licensing window for new Urban Co-operative Banks (UCBs) after 22 years?

22 वर्षों बाद RBI ने नए शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए लाइसेंसिंग विंडो फिर से खोलने का प्रस्ताव क्यों रखा है?

- A) To privatise Urban Co-operative Banks / शहरी सहकारी बैंकों का निजीकरण करने के लिए
- B) To increase foreign investment in UCBs / UCBs में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए
- C) After sector reforms, to allow eligible cooperative credit societies to become banks / क्षेत्रीय सुधारों के बाद योग्य सहकारी ऋण संस्थाओं को बैंक बनने की अनुमति देने के लिए
- D) Due to shortage of scheduled commercial banks / अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कमी के कारण
- E) To merge all UCBs with public sector banks / सभी UCBs को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय करने के लिए

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The RBI has proposed reopening the licensing window for new Urban Co-operative Banks after 22 years.
- RBI ने 22 वर्षों बाद नए शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया फिर से शुरू करने का प्रस्ताव दिया है।
- The previous licensing window was closed in 2004 due to widespread failures of newly licensed UCBs.
- वर्ष 2004 में नए लाइसेंस प्राप्त UCBs की व्यापक विफलताओं के कारण यह प्रक्रिया बंद कर दी गई थी।
- At that time, around 31% of newly licensed Urban Co-operative Banks had failed.
- उस समय लगभग 31% नए लाइसेंस प्राप्त शहरी सहकारी बैंक असफल हो गए थे।
- Under the proposed norms, a cooperative credit society must have a minimum capital of ₹300 crore as on March 31 of the preceding financial year to apply for a banking licence.
- प्रस्तावित नियमों के अनुसार, किसी सहकारी ऋण संस्था के पास पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक न्यूनतम ₹300 करोड़ की पूंजी होनी चाहिए।
- The assessed Capital Adequacy Ratio (CAR) should not be less than 12% at the time of grant of licence.
- लाइसेंस दिए जाने के समय आकलित पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) 12% से कम नहीं होना चाहिए।
- The net Non-Performing Assets (NPA) ratio should not exceed 3%.
- शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) का अनुपात 3% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- After multiple reforms in the cooperative banking sector, RBI is now reconsidering restarting the licensing process.





Ques : By which platform will EPFO subscribers be able to withdraw EPF money directly into their bank accounts from April?

अप्रैल से EPFO सदस्य किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे अपने बैंक खाते में EPF राशि निकाल सकेंगे?

- A) NEFT / एनईएफटी
- B) RTGS / आरटीजीएस
- C) IMPS / आईएमपीएस
- D) UPI / यूपीआई
- E) AEPS / आईपीएस

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- EPFO subscribers will be able to withdraw their Employees' Provident Fund (EPF) directly into bank accounts through the UPI payment gateway by April.
- EPFO सदस्य अप्रैल तक UPI पेमेंट गेटवे के माध्यम से सीधे अपने बैंक खाते में EPF राशि निकाल सकेंगे।
- The auto-settlement withdrawal limit has been increased from ₹1 lakh to ₹5 lakh, enabling higher instant withdrawals.
- ऑटो-सेटलमेंट निकासी सीमा को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया गया है।
- This move will allow EPFO members to access funds within three days for purposes such as illness, education, marriage, and housing.
- इस कदम से EPFO सदस्यों को बीमारी, शिक्षा, विवाह और आवास जैसे उद्देश्यों के लिए 3 दिनों के भीतर धनराशि उपलब्ध हो सकेगी।
- The Labour Ministry is working on a system where a part of EPF savings will be frozen, while a major portion will be available for quick withdrawal via UPI.
- श्रम मंत्रालय ऐसी प्रणाली पर काम कर रहा है जिसमें EPF का एक हिस्सा फ्रीज रहेगा, जबकि बड़ा हिस्सा UPI के जरिए त्वरित निकासी के लिए उपलब्ध होगा।
- The current interest rate on EPF deposits is 8.25% per annum.
- वर्तमान में EPF पर ब्याज दर 8.25% प्रति वर्ष है।





Ques : When will the Reserve Bank–Integrated Ombudsman Scheme (RB-IOS) 2026 come into effect?

रिज़र्व बैंक–एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOS) 2026 कब से प्रभावी होगी?

- A) January 1, 2026
- B) April 1, 2026
- C) July 1, 2025
- D) October 1, 2026
- E) July 1, 2026

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has issued the Reserve Bank–Integrated Ombudsman Scheme (RB-IOS) 2026, a revised grievance redressal framework aimed at simplifying complaint resolution for customers of banks and other financial institutions.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने रिज़र्व बैंक–एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOS) 2026 जारी की है, जिसका उद्देश्य बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों के लिए शिकायत निवारण प्रक्रिया को सरल बनाना है।
- The RB-IOS 2026 supersedes the earlier RB-IOS 2021 and will be effective from July 1, 2026.
- RB-IOS 2026, RB-IOS 2021 का स्थान लेगी और 1 जुलाई 2026 से लागू होगी।
- The Scheme applies to various Regulated Entities, including commercial banks, co-operative banks, eligible NBFCs, non-bank PPI issuers, and credit information companies.
- यह योजना विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी, जिनमें वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, पात्र NBFC, नॉन-बैंक PPI जारीकर्ता और क्रेडिट सूचना कंपनियाँ शामिल हैं।
- There is no monetary limit on disputes that can be taken to the RBI Ombudsman.
- RBI लोकपाल के समक्ष लाए जाने वाले विवादों की कोई राशि सीमा नहीं है।
- The compensation limit for consequential loss has been increased to ₹30 lakh (previously Rs 20 lakh), and up to ₹3 lakh (previously Rs 1 lakh), can be awarded for mental agony, harassment, and expenses.
- परिणामी नुकसान के लिए मुआवज़ा सीमा ₹30 लाख कर दी गई है, जबकि मानसिक पीड़ा, उत्पीड़न आदि के लिए ₹3 लाख तक का मुआवज़ा दिया जा सकता है।
- RBI will set up a Centralised Receipt and Processing Centre (CRPC) for handling complaints under the scheme.
- RBI शिकायतों की प्राप्ति और प्रसंस्करण के लिए केंद्रीकृत प्राप्ति एवं प्रसंस्करण केंद्र (CRPC) स्थापित करेगा।



Ques : When will the Reserve Bank–Integrated Ombudsman Scheme (RB-IOS) 2026 come into effect?

रिज़र्व बैंक–एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOS) 2026 कब से प्रभावी होगी?

- A) January 1, 2026
- B) April 1, 2026
- C) July 1, 2025
- D) October 1, 2026
- E) July 1, 2026

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has issued the Reserve Bank–Integrated Ombudsman Scheme (RB-IOS) 2026, a revised grievance redressal framework aimed at simplifying complaint resolution for customers of banks and other financial institutions.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने रिज़र्व बैंक–एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOS) 2026 जारी की है, जिसका उद्देश्य बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों के लिए शिकायत निवारण प्रक्रिया को सरल बनाना है।
- The RB-IOS 2026 supersedes the earlier RB-IOS 2021 and will be effective from July 1, 2026.
- RB-IOS 2026, RB-IOS 2021 का स्थान लेगी और 1 जुलाई 2026 से लागू होगी।
- The Scheme applies to various Regulated Entities, including commercial banks, co-operative banks, eligible NBFCs, non-bank PPI issuers, and credit information companies.
- यह योजना विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी, जिनमें वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, पात्र NBFC, नॉन-बैंक PPI जारीकर्ता और क्रेडिट सूचना कंपनियाँ शामिल हैं।
- There is no monetary limit on disputes that can be taken to the RBI Ombudsman.
- RBI लोकपाल के समक्ष लाए जाने वाले विवादों की कोई राशि सीमा नहीं है।
- The compensation limit for consequential loss has been increased to ₹30 lakh (previously Rs 20 lakh), and up to ₹3 lakh (previously Rs 1 lakh), can be awarded for mental agony, harassment, and expenses.
- परिणामी नुकसान के लिए मुआवज़ा सीमा ₹30 लाख कर दी गई है, जबकि मानसिक पीड़ा, उत्पीड़न आदि के लिए ₹3 लाख तक का मुआवज़ा दिया जा सकता है।
- RBI will set up a Centralised Receipt and Processing Centre (CRPC) for handling complaints under the scheme.
- RBI शिकायतों की प्राप्ति और प्रसंस्करण के लिए केंद्रीकृत प्राप्ति एवं प्रसंस्करण केंद्र (CRPC) स्थापित करेगा।



Ques: Public Sector Banks (PSBs) sanctioned over 3.96 lakh MSME loan applications worth more than ₹52,300 crore under which digital initiative during April–December 2025?

अप्रैल–दिसंबर 2025 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने किस डिजिटल पहल के तहत 3.96 लाख से अधिक MSME ऋण आवेदन स्वीकृत किए?

- A) Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) / आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना
- B) Jan Samarth Portal / जन समर्थ पोर्टल
- C) Credit Assessment Model (CAM) based digital underwriting / क्रेडिट असेसमेंट मॉडल (CAM) आधारित डिजिटल अंडरराइटिंग
- D) MSME Credit Guarantee Scheme / MSME क्रेडिट गारंटी योजना
- E) Account Aggregator Framework / अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Public Sector Banks sanctioned over 3.96 lakh MSME loan applications amounting to more than ₹52,300 crore between April 1 and December 31, 2025.
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2025 के बीच 3.96 लाख से अधिक MSME ऋण आवेदन, ₹52,300 करोड़ से अधिक राशि के, स्वीकृत किए।
- These loans were sanctioned under digital credit underwriting programmes.
- ये ऋण डिजिटल क्रेडिट अंडरराइटिंग कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वीकृत किए गए।
- In 2025, PSBs launched the Credit Assessment Model (CAM) for MSMEs.
- वर्ष 2025 में PSBs ने MSMEs के लिए क्रेडिट असेसमेंट मॉडल (CAM) शुरू किया।
- CAM is based on digital footprints of Micro, Small and Medium Enterprises.
- CAM सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के डिजिटल फुटप्रिंट पर आधारित है।
- The initiative aims to enable faster, data-driven and transparent credit flow to MSMEs.
- इस पहल का उद्देश्य MSMEs को तेज़, डेटा-आधारित और पारदर्शी ऋण उपलब्ध कराना है।





Recent News Headlines Related to First in india and world :

- Tamil Nadu has unveiled India's first Deep Tech Startup Policy 2025–26 to promote cutting-edge research and innovation. The policy earmarks an investment of ₹100 crore to support 100 deeptech start-ups across the state.
- तमिलनाडु ने अत्याधुनिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप नीति 2025-26 का अनावरण किया है। इस नीति के तहत राज्य भर में 100 डीपटेक स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए 100 करोड़ रुपये का निवेश निर्धारित किया गया है।
- Indian Institute of Information Technology, Dharwad (IIIT-D) will deploy India's first commercial quantum computer at its Centre for Excellence in Quantum AI and Computing. The deployment will be carried out in collaboration with Bengaluru-based deeptech startup QpiAI.
- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ (IIIT-D) अपने क्वांटम एआई और कंप्यूटिंग उत्कृष्टता केंद्र में भारत का पहला वाणिज्यिक क्वांटम कंप्यूटर स्थापित करेगा। यह स्थापना बेंगलुरु स्थित डीपटेक स्टार्टअप QpiAI के सहयोग से की जाएगी।
- Union Minister of State (Independent Charge) Dr. Jitendra Singh launched India's first open-sea Marine Fish Farming Project (MFFP).
- केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली ओपन-सी मरीन फिश फार्मिंग परियोजना (MFFP) का शुभारंभ किया।
- India's postal network has taken a major digital leap by delivering its first ONDC order.
- भारत के डाक नेटवर्क ने अपना पहला ONDC ऑर्डर डिलीवर कर एक बड़ी डिजिटल छलांग लगाई है।
- India marked a major milestone in judicial reform with the virtual inauguration of the country's first fully paperless district judiciary at Kalpetta in Wayanad district, Kerala.
- भारत ने न्यायिक सुधार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जब केरल के वायनाड ज़िले के कल्पेट्टा में देश की पहली पूरी तरह पेपरलेस जिला न्यायपालिका का वर्चुअल उद्घाटन किया गया।
- The newly formed Keyi Panyor district in Arunachal Pradesh is set to become India's first Bio-Happy District, marking a pioneering effort to integrate biodiversity conservation with human well-being.
- अरुणाचल प्रदेश का नवगठित कीयी पन्योर जिला भारत का पहला बायो-हैप्पी जिला बनने जा रहा है, जो जैव विविधता संरक्षण और मानव कल्याण को एकीकृत करने का एक अभिनव प्रयास है।





Ques : Which foreign bank has received approval to acquire a majority stake in RBL Bank Limited?

किस विदेशी बैंक को RBL बैंक लिमिटेड में बहुमत हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी मिली है?

- A) Emirates NBD Bank / एमिरेट्स NBD बैंक
- B) Standard Chartered Bank / स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
- C) HSBC Bank / एचएसबीसी बैंक
- D) DBS Bank / डीबीएस बैंक
- E) Barclays Bank / बार्कलेज बैंक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

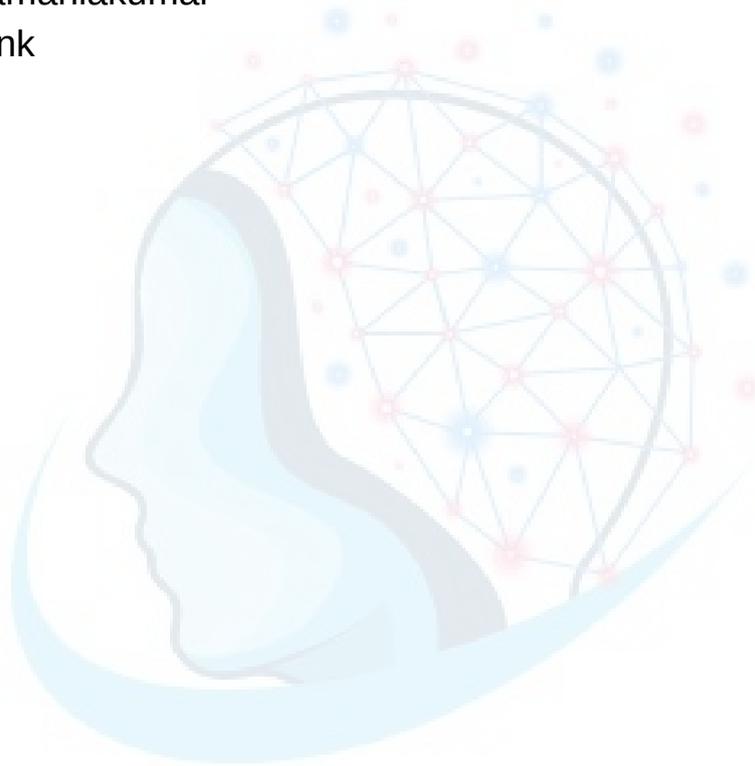
- The Commission has approved the proposed acquisition of shareholding in RBL Bank Limited by Emirates NBD Bank (P.J.S.C.).
- आयोग ने एमिरेट्स NBD बैंक (P.J.S.C.) द्वारा RBL बैंक लिमिटेड में हिस्सेदारी अधिग्रहण को मंजूरी दी है।
- The proposed combination involves acquisition of up to 74% (minimum 51%) shareholding in RBL Bank.
- प्रस्तावित सौदे के तहत RBL बैंक में न्यूनतम 51% और अधिकतम 74% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया जाएगा।
- This acquisition will be carried out through a mandatory open offer (up to 26%) under SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, along with a preferential allotment of up to 60% equity shares.
- यह अधिग्रहण SEBI (SAST) विनियम, 2011 के तहत अनिवार्य ओपन ऑफर (26% तक) और प्राथमिक आवंटन (60% तक इक्विटी शेयर) के माध्यम से किया जाएगा।
- Additionally, Emirates NBD's banking operations in India, currently operating through three branches, will be amalgamated with RBL Bank on a going concern basis.
- इसके अतिरिक्त, भारत में एमिरेट्स NBD की तीन शाखाओं के माध्यम से संचालित बैंकिंग परिचालन को RBL बैंक में विलय किया जाएगा।
- Emirates NBD Bank is a public joint stock company, listed on the Dubai Financial Market, and is headquartered in Dubai, UAE.
- एमिरेट्स NBD बैंक एक पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी है, जो दुबई फाइनेंशियल मार्केट में सूचीबद्ध है और इसका मुख्यालय दुबई, UAE में स्थित है।





About RBL Bank Limited:

- Established : 1943
- HQ : Mumbai, Maharashtra
- MD & CEO : R Subramaniakumar
- Tagline : Apno ka bank



EXAM
Genius





Ques : The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises has approved two new MSME Technology Centres in which state?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने दो नए MSME टेक्नोलॉजी सेंटर किस राज्य में स्वीकृत किए हैं?

- A) Uttarakhand / उत्तराखंड
- B) Punjab / पंजाब
- C) Himachal Pradesh / हिमाचल प्रदेश
- D) Haryana / हरियाणा
- E) Jammu & Kashmir / जम्मू और कश्मीर

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) has approved two MSME Technology Centres (TCs) in Himachal Pradesh.
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में दो MSME टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी है।
- These centres will be established at the Pandoga area in Una district and the Parwanoo industrial area in Solan district.
- ये केंद्र ऊना ज़िले के पंडोगा क्षेत्र और सोलन ज़िले के परवाणू औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे।
- The approvals are part of the 13 new Technology Centre–Extension Centres being set up across the country.
- ये स्वीकृतियाँ देशभर में स्थापित किए जा रहे 13 नए टेक्नोलॉजी सेंटर–एक्सटेंशन सेंटर का हिस्सा हैं।
- The MSME Technology Centres aim to provide advanced technology access, skilled manpower, and specialised technical services to MSMEs.
- MSME टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्देश्य MSMEs को उन्नत तकनीक, कुशल मानव संसाधन और विशेष तकनीकी सेवाएँ उपलब्ध कराना है।
- This initiative is expected to strengthen innovation, productivity, and competitiveness of MSMEs, especially in industrial clusters.
- यह पहल विशेष रूप से औद्योगिक क्लस्टरों में MSMEs की नवाचार क्षमता, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करेगी।





Ques : On which route was India's first Vande Bharat Sleeper Train flagged off by Prime Minister Narendra Modi?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किस मार्ग पर हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई?

- A) Delhi – Mumbai / दिल्ली – मुंबई
- B) Chennai – Bengaluru / चेन्नई – बेंगलुरु
- C) Howrah – Guwahati / हावड़ा – गुवाहाटी
- D) Patna – Ranchi / पटना – रांची
- E) Hyderabad – Visakhapatnam / हैदराबाद – विशाखापत्तनम

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Prime Minister Narendra Modi flagged off India's first Vande Bharat Sleeper Train between Howrah and Guwahati (Kamakhya) from Malda Town Railway Station.
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से हावड़ा-गुवाहाटी (कामाख्या) मार्ग पर भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई।
- The train is fully air-conditioned and offers an airline-like travel experience at economical fares.
- यह ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित है और किफायती किराए पर एयरलाइन जैसी यात्रा सुविधा प्रदान करती है।
- The Vande Bharat Sleeper has 16 modern coaches with a total passenger capacity of 823.
- वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में 16 आधुनिक कोच हैं, जिनकी कुल यात्री क्षमता 823 है।
- The train will benefit students, professionals, migrant workers, traders, and pilgrims travelling on this busy corridor.
- यह ट्रेन इस व्यस्त मार्ग पर यात्रा करने वाले छात्रों, पेशेवरों, प्रवासी श्रमिकों, व्यापारियों और तीर्थयात्रियों के लिए लाभकारी होगी।
- The Howrah–Guwahati route is one of India's most important railway corridors, connecting eastern and northeastern India.
- हावड़ा-गुवाहाटी मार्ग भारत के सबसे महत्वपूर्ण रेल कॉरिडोरों में से एक है।
- The new sleeper train will reduce travel time from 17 hours (Saraighat Express) to 14 hours.
- नई स्लीपर ट्रेन यात्रा समय को 17 घंटे (सरायघाट एक्सप्रेस) से घटाकर 14 घंटे कर देगी।
- Reduced travel time is expected to boost trade, tourism, and employment in the region.
- यात्रा समय में कमी से व्यापार, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। डी दिखाएंगे।





- During the event, the Prime Minister also laid the foundation stone of four major railway projects in West Bengal.
- इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में चार प्रमुख रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी।
- PM Modi will also flag off four new Amrit Bharat Express trains from Malda.
- प्रधानमंत्री मालदा से चार नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झं



EXAM
Genius





Recent Headlines Related to Inauguration :

- Union Home Minister Amit Shah laid the foundation stone of a BSL-4 (Bio-Safety Level-4) containment facility in Gandhinagar, Gujarat.
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर, गुजरात में BSL-4 (बायो-सेफ्टी लेवल-4) कंटेनमेंट सुविधा का शिलान्यास किया।
- Galgotias University inaugurated the IIT-Mandi Catalyst Satellite Centre at its campus in Greater Noida, Uttar Pradesh.
- गलगोटियास विश्वविद्यालय ने ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश स्थित अपने परिसर में IIT-मंडी कैटलिस्ट सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन किया।
- Union Minister of Home Affairs Amit Shah inaugurated a high-tech Integrated Command and Control Centre (ICCC) in the Andaman and Nicobar Islands.
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में एक हाई-टेक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) का उद्घाटन किया।
- Union Home Minister Amit Shah inaugurated the National Improvised Explosive Device Data Management System (NIDMS) of the National Security Guard (NSG).
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) की राष्ट्रीय IED डेटा प्रबंधन प्रणाली (NIDMS) का उद्घाटन किया।
- Union Minister of State Dr. Jitendra Singh from the Ministry of Science and Technology inaugurated the National Environmental Standard Laboratory and the National Primary Standard Facility for Solar Cell Calibration.
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला और सौर सेल अंशांकन हेतु राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा का उद्घाटन किया।
- Union Minister Rajiv Ranjan Singh (Lalan Singh) inaugurated the Smart Green Aquaculture Farm and India's first commercial-scale tropical RAS-based Rainbow Trout Aquaculture Farm and Research Institute in Kandukur Mandal, Ranga Reddy district, Telangana.
- केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) ने तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले के कंदुकुर मंडल में स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर फार्म और भारत के पहले वाणिज्यिक स्तर के उष्णकटिबंधीय RAS-आधारित रेनबो ट्राउट एक्वाकल्चर फार्म एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया।





Ques : According to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, what was the total area sown under rabi crops in India as on January 9, 2026?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार 9 जनवरी 2026 तक भारत में रबी फसलों के अंतर्गत कुल बोया गया क्षेत्र कितना था?

- A) 62.60 million hectares / 62.60 मिलियन हेक्टेयर
- B) 63.78 million hectares / 63.78 मिलियन हेक्टेयर
- C) 64.42 million hectares / 64.42 मिलियन हेक्टेयर
- D) 65.10 million hectares / 65.10 मिलियन हेक्टेयर
- E) 66.00 million hectares / 66.00 मिलियन हेक्टेयर

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या

- The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare released data on rabi crop area coverage as on January 9, 2026.
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 9 जनवरी 2026 तक की रबी फसलों के क्षेत्रफल से संबंधित आँकड़े जारी किए।
- The total area sown under rabi crops increased by 2.8% (1.76 million hectares) to 64.42 million hectares, compared to 62.6 million hectares during the same period last year.
- रबी फसलों के अंतर्गत कुल बोया गया क्षेत्र 2.8% (1.76 मिलियन हेक्टेयर) बढ़कर 64.42 मिलियन हेक्टेयर हो गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 62.6 मिलियन हेक्टेयर था।
- The current rabi sowing has also surpassed the seasonal average of 63.78 million hectares.
- वर्तमान रबी बुवाई क्षेत्र 63.78 मिलियन हेक्टेयर के मौसमी औसत से भी अधिक है।
- The area under wheat increased by 6.13 lakh hectares, reaching 33.42 million hectares in the 2025–26 rabi season.
- गेहूँ के अंतर्गत क्षेत्रफल 6.13 लाख हेक्टेयर बढ़कर 33.42 मिलियन हेक्टेयर हो गया।
- The area under rice stood at 2.17 million hectares during the 2025–26 rabi season.
- धान का कुल क्षेत्रफल 2.17 मिलियन हेक्टेयर रहा।
- The total area under pulses increased from 13.2 million hectares (2024–25) to 13.64 million hectares (2025–26), mainly driven by chana (gram), which rose to 9.58 million hectares.
- दलहनों का क्षेत्रफल 13.2 से बढ़कर 13.64 मिलियन हेक्टेयर हो गया, जिसमें प्रमुख योगदान चना का रहा (9.58 मिलियन हेक्टेयर)।





Ques: Prime Minister Narendra Modi performed the Bhoomi Pujan of which major highway project in Assam aimed at improving connectivity while protecting wildlife?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में किस प्रमुख राजमार्ग परियोजना का भूमि पूजन किया, जिसका उद्देश्य संपर्क सुधार के साथ वन्यजीव संरक्षण है?

- A) Brahmaputra River Bridge Project / ब्रह्मपुत्र नदी पुल परियोजना
- B) Guwahati Ring Road Project / गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना
- C) Upper Assam Expressway Project / अपर असम एक्सप्रेसवे परियोजना
- D) East–West Corridor Extension / ईस्ट–वेस्ट कॉरिडोर विस्तार
- E) Kaziranga Elevated Corridor Project (NH-715) / काज़ीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना (NH-715)

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- Prime Minister Shri Narendra Modi performed the Bhoomi Pujan of the Kaziranga Elevated Corridor Project, involving the 4-laning of the Kaliabor–Numaligarh section of NH-715, worth over ₹6,950 crore, in Kaliabor, Assam.
- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कालीआबोर, असम में ₹6,950 करोड़ से अधिक लागत वाली NH-715 के कालीआबोर–नुमालीगढ़ खंड की 4-लेनिंग से जुड़ी काज़ीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन किया।
- The Prime Minister had attended the Jhumoir Mahotsav last year and visited Assam this time during the Magh Bihu festival.
- प्रधानमंत्री पिछले वर्ष झुमोइर महोत्सव में शामिल हुए थे और इस बार माघ बिहू के अवसर पर असम पहुंचे।
- The project will significantly improve connectivity across Upper Assam, particularly benefiting Dibrugarh and Tinsukia.
- यह परियोजना ऊपरी असम में संपर्क व्यवस्था को काफी बेहतर बनाएगी, विशेष रूप से डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया को लाभ पहुंचाएगी।
- The 86 km long project is an environmentally conscious National Highway initiative, featuring a 35 km Elevated Wildlife Corridor through Kaziranga National Park.
- 86 किमी लंबी यह परियोजना एक पर्यावरण-अनुकूल राष्ट्रीय राजमार्ग पहल है, जिसमें काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाला 35 किमी लंबा एलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर शामिल है।
- The corridor will pass through Nagaon, Karbi Anglong and Golaghat districts, ensuring improved regional connectivity while safeguarding Kaziranga's unique biodiversity.
- यह कॉरिडोर नागांव, कार्बी आंगलोंग और गोलाघाट जिलों से होकर गुजरेगा और काज़ीरंगा की विशिष्ट जैव विविधता की रक्षा करते हुए क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करेगा।





Ques : The Medium Calibre Ammunition Manufacturing Facility inaugurated by Union Defence Minister Rajnath Singh is located at which place?

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उद्घाटित मध्यम कैलिबर गोला-बारूद निर्माण सुविधा कहाँ स्थित है?

- A) Kanpur, Uttar Pradesh / कानपुर, उत्तर प्रदेश
- B) Pune, Maharashtra / पुणे, महाराष्ट्र
- C) Nagpur, Maharashtra / नागपुर, महाराष्ट्र
- D) Hyderabad, Telangana / हैदराबाद, तेलंगाना
- E) Bengaluru, Karnataka / बेंगलुरु, कर्नाटक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Union Minister Rajnath Singh, Ministry of Defence, inaugurated a Medium Calibre Ammunition Manufacturing Facility at Solar Defence and Aerospace Limited (SDAL).
- केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड (SDAL) में मध्यम कैलिबर गोला-बारूद निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया।
- The facility is located in Nagpur, Maharashtra and is fully automated.
- यह सुविधा नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है और पूरी तरह स्वचालित है।
- The plant will manufacture 30 millimetre (mm) ammunition, which is extensively used by the Indian Army (IA) and the Indian Navy (IN).
- यह संयंत्र 30 मिमी गोला-बारूद का निर्माण करेगा, जिसका उपयोग भारतीय सेना और भारतीय नौसेना द्वारा व्यापक रूप से किया जाता है।
- India's domestic defence production has increased significantly from ₹46,425 crore in 2014 to a record around ₹1.51 lakh crore in 2025–26, with the private sector contributing over ₹33,000 crore.
- भारत का घरेलू रक्षा उत्पादन 2014 में ₹46,425 करोड़ से बढ़कर 2025–26 में लगभग ₹1.51 लाख करोड़ हो गया है, जिसमें निजी क्षेत्र का योगदान ₹33,000 करोड़ से अधिक है।
- Defence exports have also seen a sharp rise, reaching ₹24,000 crore, compared to less than ₹1,000 crore a decade ago.
- रक्षा निर्यात भी तेज़ी से बढ़कर ₹24,000 करोड़ हो गया है, जो एक दशक पहले ₹1,000 करोड़ से भी कम था।





Ques: Who has been appointed as India's next High Commissioner to New Zealand?

न्यूज़ीलैंड में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- A) Amit Kumar Mishra / अमित कुमार मिश्रा
- B) Muanpuii Saiawi / मुआनपुई सैआवी
- C) Ruchira Kamboj / रुचिरा कंबोज
- D) Sanjay Verma / संजय वर्मा
- E) Vinay Mohan Kwatra / विनय मोहन क्वात्रा

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Muanpuii Saiawi has been appointed as India's next High Commissioner to New Zealand.
- मुआनपुई सैआवी को न्यूज़ीलैंड में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है।
- She will represent India's diplomatic interests in New Zealand.
- वह न्यूज़ीलैंड में भारत के राजनयिक हितों का प्रतिनिधित्व करेंगी।
- Amit Kumar Mishra has been appointed as India's next Ambassador to Georgia.
- अमित कुमार मिश्रा को जॉर्जिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है।
- He will strengthen bilateral relations between India and Georgia.
- वह भारत और जॉर्जिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेंगे।

EXAM
Genius





Recently appointed ambassador:

- Stefan Priesner of Austria : United Nations Resident Coordinator in India
- ऑस्ट्रिया के स्टेफन प्राइसनेर : भारत में संयुक्त राष्ट्र रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया
- Sergio Gor : United States Ambassador to India and special envoy to South and Central Asia
- सर्जियो गोर: भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशिया के लिए विशेष दूत
- Manish Gupta : Ambassador of India to Ireland
- मनीष गुप्ता: आयरलैंड में भारत के राजदूत
- Senior Indian Foreign Service officer Gourangalal Das : India's next ambassador to South Korea
- वरिष्ठ भारतीय विदेश सेवा अधिकारी गौरंगलाल दास : भारत के अगले दक्षिण कोरिया राजदूत
- Dr. Deepak Mittal : India's next Ambassador to the United Arab Emirates (succeeding Sunjay Sudhir)
- डॉ. दीपक मित्तल : संयुक्त अरब अमीरात के लिए भारत के अगले राजदूत (संजय सुधीर का स्थान लेंगे)
- Dinesh K Patnaik : India's High Commissioner to Canada
- दिनेश के. पट्टनाइक : कनाडा के लिए भारत के उच्चायुक्त
- Sergio Gor : US ambassador to India
- सर्जियो गोर : भारत में अमेरिका के राजदूत
- Aliawati Longkumer : Ambassador to North Korea from India
- एलियावती लॉन्गकुमेर : भारत से उत्तर कोरिया के लिए राजदूत
- Anurag Bhushan : Ambassador of India to the Kingdom of Sweden (Replaced Tanmaya Lal)
- अनुराग भूषण : स्वीडन राज्य में भारत के राजदूत (तनमय लाल का स्थान लिया)
- Jitender Pal Singh : Ambassador to Israel (Replaced Sanjeev Kumar Singla)
- जितेन्द्र पाल सिंह : इज़राइल के लिए भारत के राजदूत (संजय कुमार सिंगला का स्थान लिया)





Ques: Which two organisations signed an MoU to enable multilingual translation and AI-powered language support across Ayushman Bharat digital health platforms?

आयुष्मान भारत की डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों में बहुभाषी अनुवाद और AI-आधारित भाषा सहायता के लिए किन दो संस्थानों के बीच MoU पर हस्ताक्षर किए गए?

- A) Ministry of Health & Family Welfare and NITI Aayog / स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और नीति आयोग
- B) National Health Authority and Digital India BHASHINI Division / राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन
- C) National Health Authority and UIDAI / राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और यूआईडीएआई
- D) Digital India Corporation and AIIMS / डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन और एम्स
- E) Ministry of Electronics & IT and WHO / इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Digital India BHASHINI Division participated in the Chintan Shivir – National Review of Ayushman Bharat PM-JAY and Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) held in Bhubaneswar, Odisha.
- डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन ने भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित आयुष्मान भारत PM-JAY और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) की राष्ट्रीय समीक्षा हेतु चिंतन शिविर में भाग लिया।
- During the event, a Memorandum of Understanding (MoU) was signed between the National Health Authority (NHA) and the Digital India BHASHINI Division.
- इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) और डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
- The MoU aims to enable multilingual translation services and AI-powered language support across NHA's digital health platforms, including AB PM-JAY and ABDM.
- इस MoU का उद्देश्य AB PM-JAY और ABDM सहित NHA की डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों में बहुभाषी अनुवाद सेवाएँ और AI-आधारित भाषा सहायता उपलब्ध कराना है।
- This collaboration will help improve accessibility, inclusivity, and citizen-centric delivery of digital health services across India.



Ques : What is the main objective of the proposed Integrated Fisheries Hub in Lakshadweep?

लक्षद्वीप में प्रस्तावित एकीकृत मत्स्य हब का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- A) Promoting inland fisheries / आंतरिक मत्स्य पालन को बढ़ावा देना
- B) Single-window system to streamline fish marketing and strengthen the value chain / मछली विपणन को सुव्यवस्थित करने और मूल्य शृंखला को मजबूत करने हेतु सिंगल-विंडो प्रणाली
- C) Replacing traditional fishing methods / पारंपरिक मछली पकड़ने की विधियों को समाप्त करना
- D) Restricting fish exports / मछली निर्यात को सीमित करना
- E) Focus only on ornamental fisheries / केवल सजावटी मत्स्य पालन पर ध्यान देना

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Matsya Mela concluded at Kavaratti with a call to establish an Integrated Fisheries Hub in Lakshadweep.
- कवारत्ती में आयोजित मत्स्य मेला का समापन लक्षद्वीप में एकीकृत मत्स्य हब स्थापित करने की मांग के साथ हुआ।
- The proposed hub will function as a single-window platform for organised fish marketing.
- प्रस्तावित हब संगठित मछली विपणन के लिए सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा।
- It aims to strengthen the fisheries value chain and enhance income and livelihood security of island fishing communities.
- इसका उद्देश्य मत्स्य मूल्य शृंखला को मजबूत करना और द्वीपीय मछुआरा समुदायों की आय एवं आजीविका सुरक्षा बढ़ाना है।
- Key focus areas include common landing and handling facilities, cold storage, cold-chain infrastructure, value addition units, and export facilitation.
- प्रमुख फोकस क्षेत्रों में सामान्य लैंडिंग व हैंडलिंग सुविधाएँ, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड-चेन अवसंरचना, वैल्यू एडिशन यूनिट्स और निर्यात सुविधा शामिल हैं।
- The hub is expected to unlock the full potential of Lakshadweep's tuna-based fisheries and mariculture sectors.
- यह हब लक्षद्वीप की ट्यूना आधारित मत्स्य पालन और मैरिकल्चर क्षेत्रों की पूर्ण क्षमता को उजागर करेगा।
- Stakeholders highlighted the need for scientific estimation of fish catch data to





ensure sustainable fisheries management.

- हितधारकों ने सतत मत्स्य प्रबंधन के लिए मछली पकड़ के वैज्ञानिक आकलन पर ज़ोर दिया।
- The event was organised by KVK Lakshadweep (ICAR–CMFRI) in association with the Fisheries Department of Lakshadweep.
- इस कार्यक्रम का आयोजन केवीके लक्षद्वीप (ICAR–CMFRI) द्वारा लक्षद्वीप मत्स्य विभाग के सहयोग से किया गया।



EXAM
Genius





Ques : The “One Station One Product” (OSOP) initiative is implemented by which organisation?

“वन स्टेशन वन प्रोडक्ट” (OSOP) पहल किस संगठन द्वारा लागू की जा रही है?

- A) Ministry of MSME / सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
- B) Ministry of Railways / रेल मंत्रालय
- C) Ministry of Commerce and Industry / वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
- D) NITI Aayog / नीति आयोग
- E) Indian Railways / भारतीय रेलवे

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- Indian Railways' One Station One Product (OSOP) scheme has emerged as a powerful platform for promoting local craftsmanship and grassroots entrepreneurship across the country.
- भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट (OSOP) योजना स्थानीय शिल्पकला और जमीनी स्तर के उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने वाला एक प्रभावशाली मंच बनकर उभरी है।
- The initiative aims to transform railway stations into vibrant showcases of India's rich regional diversity, integrating local heritage with the national railway network.
- इस पहल का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों को भारत की समृद्ध क्षेत्रीय विविधता के जीवंत प्रदर्शन केंद्रों में बदलना है, जिससे स्थानीय विरासत को राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा सके।
- OSOP not only enhances passenger experience but also supports inclusive economic growth by providing market access to local producers.
- OSOP यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के साथ-साथ समावेशी आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देता है।
- As of 19 January 2026, OSOP outlets have been set up at 2,002 stations, with a total of 2,326 outlets operational across India.
- 19 जनवरी 2026 तक, 2,002 रेलवे स्टेशनों पर 2,326 OSOP आउटलेट्स स्थापित किए जा चुके हैं।
- These outlets have become a major source of livelihood for thousands of local artisans, weavers, and small producers, connecting them directly with millions of passengers every day.
- ये आउटलेट्स स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और छोटे उत्पादकों के लिए आजीविका का महत्वपूर्ण साधन बने हैं, जिन्हें प्रतिदिन लाखों यात्रियों से सीधा संपर्क मिलता है।





- Since its launch in 2022, the OSOP initiative has created direct economic opportunities for over 1.32 lakh beneficiaries across the country.
- 2022 में शुरू होने के बाद से, OSOP पहल ने देशभर में 1.32 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए प्रत्यक्ष आर्थिक अवसर सृजित किए हैं।
- By integrating commerce with culture, Indian Railways has transformed stations into hubs of local enterprise, making OSOP a strong example of “Vocal for Local.”
- व्यापार को संस्कृति से जोड़ते हुए, भारतीय रेलवे ने स्टेशनों को स्थानीय उद्यमिता के केंद्र में बदल दिया है, जिससे OSOP “वोकल फॉर लोकल” का उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है।
- The initiative empowers local communities while enriching the travel experience for passengers across the nation.
- यह पहल स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाते हुए देशभर के यात्रियों के यात्रा अनुभव को समृद्ध करती है।

EXAM
Genius





Ques : Who has been nominated as Chair of the UN Advisory Board on Disarmament Matters for the 2026–27 term?

2026–27 अवधि के लिए यूएन निरस्त्रीकरण सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है?

- A) Ruchira Kamboj / रुचिरा कंबोज
- B) D.B. Venkatesh Varma / डी.बी. वेंकटेश वर्मा
- C) Syed Akbaruddin / सैयद अकबरुद्दीन
- D) Vikram Misri / विक्रम मिस्त्री
- E) Nirupama Rao / निरुपमा राव

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Senior Indian diplomat D.B. Venkatesh Varma has been nominated by the UN Secretary-General as Chair of the Advisory Board on Disarmament Matters for the 2026–27 term.
- वरिष्ठ भारतीय राजनयिक डी.बी. वेंकटेश वर्मा को संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा 2026–27 अवधि के लिए निरस्त्रीकरण मामलों के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया है।
- This appointment marks the first time an Indian has been named Chair of this UN body.
- यह पहली बार है जब किसी भारतीय को इस यूएन निकाय का अध्यक्ष बनाया गया है।
- The Advisory Board on Disarmament Matters was established in 1978.
- निरस्त्रीकरण मामलों का सलाहकार बोर्ड वर्ष 1978 में स्थापित किया गया था।
- Earlier, Indian diplomats had served as members of the board, but never as Chair.
- इससे पहले भारतीय राजनयिक बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं, लेकिन अध्यक्ष पद पर कभी नहीं रहे।
- D.B. Venkatesh Varma is a former Indian Ambassador to Russia and a noted expert in disarmament and strategic affairs.
- डी.बी. वेंकटेश वर्मा रूस में भारत के पूर्व राजदूत रह चुके हैं और निरस्त्रीकरण एवं रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं।





Ques: What is India's global rank in the Responsible Nations Index (RNI) 2026?

रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स (RNI) 2026 में भारत की वैश्विक रैंक क्या है?

- A) 10th
- B) 12th
- C) 16th
- D) 25th
- E) 38th

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

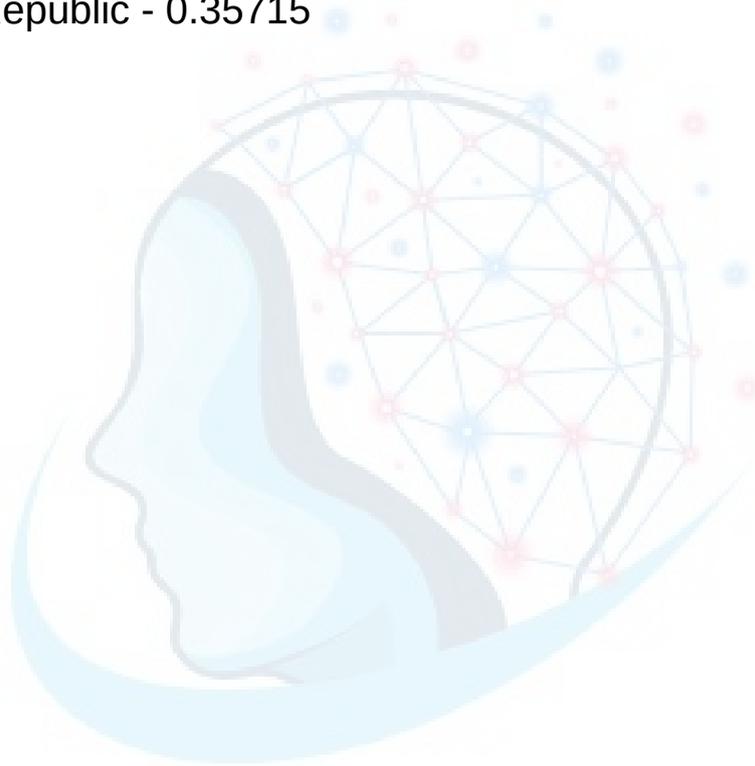
- The Responsible Nations Index (RNI) was released in its 1st edition.
- रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स (RNI) का पहला संस्करण जारी किया गया।
- The index is published by the World Intellectual Foundation (WIF), Jawaharlal Nehru University (JNU), and Indian Institute of Management (IIM) Mumbai.
- यह सूचकांक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन (WIF), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) मुंबई द्वारा प्रकाशित किया गया है।
- RNI is based on three pillars: Internal Responsibility, Environmental Responsibility, and External Responsibility.
- RNI तीन स्तंभों पर आधारित है: आंतरिक उत्तरदायित्व, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व और बाह्य उत्तरदायित्व।
- India ranked 16th globally in RNI 2026 with an overall score of 0.551513.
- RNI 2026 में भारत ने 0.551513 के कुल स्कोर के साथ वैश्विक स्तर पर 16वां स्थान प्राप्त किया।
- Singapore topped the index among 154 countries with an overall score of 0.61945.
- Major economies ranked as follows: Japan (38th), USA (66th), and China (68th).
- 154 देशों में सिंगापुर ने 0.61945 के स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में जापान 38वें, अमेरिका 66वें और चीन 68वें स्थान पर रहे।

Top Countries of Responsible Nations Index (RNI) with Score :

- 1 Singapore - 0.61945
- 2 Switzerland - 0.58692
- 3 Denmark - 0.58372



- 4 Cyprus - 0.57737
- 5 Sweden - 0.57387
- 16 India - 0.551513
- 152 South Sudan - 0.37389
- 153 Syria - 0.37254
- 154 Central African Republic - 0.35715



EXAM
Genius





Recent News Headlines Related to MoU and agreement:

- India and Germany are close to finalising a submarine manufacturing deal worth around \$8 billion, which could become India's largest-ever defence agreement.
- भारत और जर्मनी लगभग \$8 अरब की पनडुब्बी निर्माण डील को अंतिम रूप देने के करीब हैं, जो भारत की अब तक की सबसे बड़ी रक्षा डील हो सकती है।
- Digital India BHASHINI (BHASHa INterface for India) signed an agreement with the Government of Madhya Pradesh.
- डिजिटल इंडिया भाषिणी (BHASHA इंटरफेस फॉर इंडिया) ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- An agreement was signed between India and Israel at the Second Global Summit on "Blue Food Security: Sea the Future 2026", held in Eilat, Israel.
- यह समझौता इज़राइल के एलियट में आयोजित "ब्लू फूड सिक्योरिटी: सी द फ्यूचर 2026" के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन में भारत और इज़राइल के बीच हस्ताक्षरित हुआ।
- India and Germany Signed a Joint Declaration of Intent (JDI) to deepen bilateral cooperation in the fields of telecommunications and Information and Communication Technologies (ICTs)
- भारत और जर्मनी ने दूरसंचार और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए एक संयुक्त आशय घोषणा पत्र (जेडीआई) पर हस्ताक्षर किए।
- Government of Tamil Nadu signed a Memorandum of Understanding with Sarvam AI to establish India's first full-stack Sovereign Artificial Intelligence Park in Chennai
- तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में भारत का पहला पूर्ण-स्तरीय संप्रभु कृत्रिम बुद्धिमत्ता पार्क स्थापित करने के लिए सर्वम एआई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- The Indian Council of Agricultural Research (ICAR) signed a Memorandum of Understanding with the National Dairy Development Board (NDDB) to strengthen collaboration in multidisciplinary research, innovation, and capacity building across the entire dairy sector.
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने पूरे डेयरी क्षेत्र में बहुविषयक अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए





Ques : The recently excavated Zehanpora Stupa site in Kashmir belongs to which historical period?

कश्मीर में हाल ही में उत्खनन किया गया ज़ेहानपोरा स्तूप स्थल किस ऐतिहासिक काल से संबंधित है?

- A) Mauryan Period / मौर्य काल
- B) Gupta Period / गुप्त काल
- C) Kushan Period / कुशाण काल
- D) Harsha Period / हर्ष काल
- E) Post-Gupta Period / उत्तर-गुप्त काल

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Zehanpora Stupa site is located in the Baramulla district of Kashmir and has been recently excavated by archaeologists.
- ज़ेहानपोरा स्तूप स्थल कश्मीर के बारामूला ज़िले में स्थित है और हाल ही में इसका पुरातात्विक उत्खनन किया गया है।
- Archaeological findings date the site to nearly 2,000 years ago, corresponding to the Kushan period (1st–3rd Century CE).
- पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार यह स्थल लगभग 2,000 वर्ष पुराना है और कुशाण काल (प्रथम–तृतीय शताब्दी ईस्वी) से संबंधित है।
- Evidence from the site indicates the presence of large stupas, monastic complexes, and urban settlements, suggesting an advanced Buddhist establishment.
- स्थल से प्राप्त साक्ष्य विशाल स्तूपों, मठ संरचनाओं और शहरी बस्तियों की उपस्थिति को दर्शाते हैं, जो एक विकसित बौद्ध केंद्र की ओर संकेत करता है।
- The discovery highlights Kashmir's rich Buddhist heritage and its role as a major cultural and religious centre in ancient India.
- यह खोज कश्मीर की समृद्ध बौद्ध विरासत और प्राचीन भारत में उसके सांस्कृतिक व धार्मिक केंद्र होने की भूमिका को उजागर करती है।
- The site also strengthens historical links between Kashmir and major Buddhist trade and learning networks of the ancient world.
- यह स्थल कश्मीर के प्रमुख बौद्ध व्यापार और ज्ञान नेटवर्क से जुड़े ऐतिहासिक संबंधों को भी सुदृढ़ करता है।





Ques: Which institution has been designated as the official examination partner for the entrance of the Post Graduate Insolvency Programme (PGIP)?

पोस्ट ग्रेजुएट इन्सॉल्वेंसी प्रोग्राम (PGIP) की प्रवेश परीक्षा के लिए आधिकारिक परीक्षा भागीदार किस संस्था को बनाया गया है?

- A) Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) / बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान
- B) Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) / भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान
- C) National Testing Agency (NTA) / राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी
- D) Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI (IIPI-ICAI) / आईसीएआई का भारतीय इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स संस्थान
- E) Reserve Bank of India (RBI) / भारतीय रिज़र्व बैंक

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- The Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) has opened registrations for the 8th Batch of the Post Graduate Insolvency Programme (PGIP).
- भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (IICA) ने पोस्ट ग्रेजुएट इन्सॉल्वेंसी प्रोग्राम (PGIP) के 8वें बैच के लिए पंजीकरण शुरू किए हैं।
- PGIP is a flagship national initiative aimed at creating highly skilled insolvency professionals in accordance with India's Insolvency and Bankruptcy Code (IBC).
- PGIP भारत के इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड (IBC) के अनुरूप उच्च कौशल वाले इन्सॉल्वेंसी पेशेवर तैयार करने की एक प्रमुख राष्ट्रीय पहल है।
- IICA has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI (IIPI-ICAI) to strengthen collaboration in insolvency and bankruptcy education, research, and training.
- IICA ने इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए ICAI के भारतीय इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स संस्थान (IIPI-ICAI) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- The Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) has been designated as the official examination partner for conducting the PGIP entrance examination.
- बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) को PGIP की प्रवेश परीक्षा के लिए आधिकारिक परीक्षा भागीदार नियुक्त किया गया है।

About IICA :



Ques : India has signed a long-term LNG supply agreement with which country to import 0.5 million metric tonnes of LNG annually?

भारत ने प्रतिवर्ष 0.5 मिलियन मीट्रिक टन LNG आयात के लिए किस देश के साथ दीर्घकालिक समझौता किया है?

- A) Saudi Arabia / सऊदी अरब
- B) Qatar / कतर
- C) United Arab Emirates / संयुक्त अरब अमीरात
- D) Oman / ओमान
- E) Russia / रूस

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- India and the United Arab Emirates (UAE) have signed a long-term Liquefied Natural Gas (LNG) supply agreement.
- भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच दीर्घकालिक LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- Under this agreement, the UAE will supply 0.5 million metric tonnes of LNG annually to India.
- इस समझौते के तहत UAE भारत को प्रतिवर्ष 0.5 मिलियन मीट्रिक टन LNG की आपूर्ति करेगा।
- With this deal, the UAE has become India's second-largest supplier of LNG, after Qatar, strengthening India's energy security.
- इस समझौते के साथ UAE, कतर के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता बन गया है।
- Beyond energy cooperation, both countries have agreed to set an ambitious bilateral trade target of USD 200 billion by 2032.
- ऊर्जा सहयोग के अलावा, दोनों देशों ने 2032 तक 200 अरब अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य पर भी सहमति व्यक्त की है।





Ques: Centre for Development of Telematics (C-DOT) received the SKOCH Award-2025 for which solution?

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DOT) को SKOCH अवार्ड-2025 किस समाधान के लिए प्रदान किया गया?

- A) BharatNet Connectivity Platform / भारतनेट कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म
- B) National Telecom Cloud / राष्ट्रीय टेलीकॉम क्लाउड
- C) Digital Disaster Portal / डिजिटल आपदा पोर्टल
- D) 5G Core Network System / 5G कोर नेटवर्क सिस्टम
- E) Cell Broadcast Solution (CBS) / सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन (CBS)

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- Centre for Development of Telematics (C-DOT) has been conferred the SKOCH Award-2025 for its Cell Broadcast Solution (CBS).
- सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DOT) को उसके सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन (CBS) के लिए SKOCH अवार्ड-2025 प्रदान किया गया है।
- The award ceremony was held during the 104th SKOCH Summit with the theme “Resourcing Viksit Bharat”.
- यह पुरस्कार “रिसोर्सिंग विकसित भारत” थीम पर आयोजित 104वें SKOCH समिट के दौरान प्रदान किया गया।
- The SKOCH Awards recognise outstanding contributions by government and private institutions in improving governance and development across sectors such as finance, technology, health, education, and grassroots initiatives.
- SKOCH अवार्ड सरकार और निजी संस्थानों द्वारा वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा और जमीनी स्तर पर शासन व विकास में किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देता है।
- C-DOT’s Cell Broadcast Solution is a unified disaster and emergency alert platform that integrates agencies such as India Meteorological Department (IMD) (weather), Central Water Commission (CWC) (floods), Indian National Centre for Ocean Information Services (INCOIS) (tsunami and ocean events), Defence Geo -informatics Research Establishment (DGRE) (landslides), and Forest Survey of India (FSI) (forest fires).





- C-DOT का सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन एक एकीकृत आपदा एवं आपातकालीन अलर्ट प्लेटफॉर्म है, जो IMD, CWC, INCOIS, DGRE और FSI जैसी एजेंसियों को जोड़ता है।
- The platform also involves mobile operators for message delivery and State Disaster Management Authorities (SDMAs) and National Disaster Management Authority (NDMA) for alert approval and disaster management.
- इसमें संदेश प्रसारण के लिए सभी मोबाइल ऑपरेटरों तथा अलर्ट स्वीकृति व आपदा प्रबंधन के लिए SDMA और NDMA शामिल हैं।
- This indigenous, cost-effective and fully automated system enables geo-targeted, near real-time, multi-hazard alerts in 21 languages through cellular networks, strengthening disaster risk reduction and management.
- यह स्वदेशी, किफायती और पूर्णतः स्वचालित प्रणाली सेलुलर नेटवर्क के माध्यम से 21 भाषाओं में स्थान-विशिष्ट, लगभग वास्तविक समय में बहु-आपदा चेतावनियाँ प्रदान कर आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन को मजबूत करती है।

EXAM
Genius





Ques : Zoho launched its new data centres in which cities of the UAE?

जोहो ने अपने नए डेटा सेंटर्स यूएई के किन शहरों में लॉन्च किए हैं?

- A) Dubai and Abu Dhabi / दुबई और अबू धाबी
- B) Sharjah and Ajman / शारजाह और अजमान
- C) Ras Al Khaimah and Fujairah / रस अल खैमाह और फुजैरा
- D) Al Ain and Umm Al Quwain / अल ऐन और उम्म अल क्वैन
- E) Dubai and Sharjah / दुबई और शारजाह

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- Chennai-based SaaS company Zoho has launched its data centres in Dubai and Abu Dhabi, UAE.
- चेन्नई स्थित SaaS कंपनी जोहो ने दुबई और अबू धाबी, यूएई में अपने डेटा सेंटर्स लॉन्च किए हैं।
- These data centres are part of Zoho's AED 100 million investment commitment in the UAE announced in 2023.
- ये डेटा सेंटर्स 2023 में घोषित यूएई में जोहो के AED 100 मिलियन निवेश का हिस्सा हैं।
- The initiative aims to strengthen Zoho's cloud infrastructure and data localization capabilities in the Middle East region.
- इस पहल का उद्देश्य मिडिल ईस्ट क्षेत्र में जोहो के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा लोकलाइजेशन क्षमताओं को मजबूत करना है।
- Local data centres will help Zoho comply with regional data protection laws and improve services for enterprise customers.
- स्थानीय डेटा सेंटर्स क्षेत्रीय डेटा संरक्षण कानूनों के अनुपालन में मदद करेंगे और एंटरप्राइज ग्राहकों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करेंगे।





Ques : Where was the foundation stone laid for the world's largest green hydrogen and green ammonia plants?

विश्व के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया संयंत्रों की आधारशिला कहाँ रखी गई?

- A) Kakinada / काकीनाडा
- B) Visakhapatnam / विशाखापत्तनम
- C) Nellore / नेल्लोर
- D) Tirupati / तिरुपति
- E) Krishnapatnam / कृष्णपट्टनम

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu laid the foundation stone for the world's largest green hydrogen and green ammonia plants at Kakinada.
- आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने काकीनाडा में विश्व के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया संयंत्रों की आधारशिला रखी।
- The green ammonia plant will be developed over an area of 495 acres, strengthening Andhra Pradesh's clean energy and green industrial growth initiatives.
- ग्रीन अमोनिया संयंत्र को 495 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा, जिससे आंध्र प्रदेश की स्वच्छ ऊर्जा और हरित औद्योगिक विकास पहलों को बल मिलेगा।
- The mega project is being developed by AM Green, a company of the Greenko Group.
- यह मेगा परियोजना ग्रीनको ग्रुप की कंपनी AM Green द्वारा विकसित की जा रही है।
- The project will transform an existing ammonia-urea complex into an integrated green hydrogen and green ammonia facility.
- यह परियोजना एक मौजूदा अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स को एकीकृत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया इकाई में परिवर्तित करेगी।
- The estimated investment in the project is around USD 10 billion, making it one of India's largest green energy investments.
- इस परियोजना में लगभग 10 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश अनुमानित है, जो इसे भारत की सबसे बड़ी हरित ऊर्जा परियोजनाओं में शामिल करता है।





Ques : The second nationwide range-wide estimation of riverine and estuarine dolphins under Project Dolphin was flagged off from which place?

प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत नदीय और मुहाना डॉल्फिन की दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गणना किस स्थान से शुरू की गई?

- A) Patna, Bihar / पटना, बिहार
- B) Varanasi, Uttar Pradesh / वाराणसी, उत्तर प्रदेश
- C) Bijnor, Uttar Pradesh / बिजनौर, उत्तर प्रदेश
- D) Guwahati, Assam / गुवाहाटी, असम
- E) Kolkata, West Bengal / कोलकाता, पश्चिम बंगाल

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Union Minister Bhupender Yadav, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), launched the second nationwide range-wide estimation of riverine and estuarine dolphins under Project Dolphin.
- केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत नदीय एवं मुहाना डॉल्फिन की दूसरी राष्ट्रीय गणना की शुरुआत की।
- The programme was flagged off from Bijnor in Uttar Pradesh.
- इस कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बिजनौर से की गई।
- Phase-I covers the main stem of the Ganga from Bijnor to Ganga Sagar and the Indus River, while Phase-II will extend to the Brahmaputra, Ganga tributaries, Sundarbans, and Odisha.
- पहला चरण गंगा की मुख्य धारा (बिजनौर से गंगासागर) और सिंधु नदी, जबकि दूसरा चरण ब्रह्मपुत्र, गंगा की सहायक नदियों, सुंदरबन और ओडिशा तक विस्तारित होगा।
- The programme builds on India's first nationwide dolphin population survey conducted during 2021–23.
- यह कार्यक्रम 2021–23 के दौरान की गई भारत की पहली राष्ट्रीय डॉल्फिन जनगणना पर आधारित है।
- The survey recorded approximately 6,327 riverine dolphins across the country.
- सर्वेक्षण में देशभर में लगभग 6,327 नदीय डॉल्फिन दर्ज की गईं।
- Uttar Pradesh and Bihar reported the highest numbers, followed by West Bengal and Assam.
- उत्तर प्रदेश और बिहार में सर्वाधिक डॉल्फिन पाई गईं, इसके बाद पश्चिम बंगाल और असम का स्थान रहा।
- The survey began with 26 researchers operating from three boats, collecting ecological and habitat data using advanced tools like hydrophones for underwater acoustic monitoring.





Ques : Pax Silica initiative, which India is set to join, is primarily related to which area?

Pax Silica पहल, जिसमें भारत को शामिल किए जाने का निमंत्रण दिया गया है, मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है?

- A) Climate change negotiations / जलवायु परिवर्तन वार्ता
- B) Defence military alliance / रक्षा सैन्य गठबंधन
- C) AI and critical technology supply chain security / AI और महत्वपूर्ण तकनीकी सप्लाई चेन सुरक्षा
- D) Global health cooperation / वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग
- E) Space exploration / अंतरिक्ष अन्वेषण

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- India will be invited to join Pax Silica, a US-led initiative focused on building secure, resilient, and innovation-driven technology and AI supply chains.
- भारत को अमेरिका-नेतृत्व वाली Pax Silica पहल में शामिल होने का निमंत्रण दिया जाएगा, जो सुरक्षित, लचीली और नवाचार-आधारित तकनीक व AI सप्लाई चेन पर केंद्रित है।
- The announcement was made by US Ambassador to India, Sergio Gor.
- इसकी घोषणा भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर द्वारा की गई।
- Pax Silica is the flagship initiative of the US State Department focusing on AI and critical technology supply chain security.
- Pax Silica, AI और महत्वपूर्ण तकनीकी सप्लाई चेन सुरक्षा पर अमेरिकी विदेश विभाग की प्रमुख (flagship) पहल है।
- The initiative aims to coordinate allied nations on semiconductors, critical minerals, artificial intelligence, and advanced technology ecosystems.
- इस पहल का उद्देश्य सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत तकनीकी इकोसिस्टम पर मित्र देशों के बीच समन्वय स्थापित करना है।
- Current members of Pax Silica include the US, Japan, South Korea, Singapore, the Netherlands, the UK, Israel, the UAE, and Australia.
- वर्तमान में Pax Silica के सदस्य अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम, इज़राइल, यूएई और ऑस्ट्रेलिया हैं।
- India was not part of the original launch, but is now expected to be included due to its growing role in global technology and supply chains.
- शुरुआती लॉन्च में भारत शामिल नहीं था, लेकिन वैश्विक तकनीक और सप्लाई चेन में बढ़ती भूमिका के कारण अब इसे शामिल किए जाने की संभावना है।



Ques: The Indian Navy's sail training ship INS Sudarshini has embarked on which flagship transoceanic expedition?

भारतीय नौसेना का नौकायन प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शिनी किस प्रमुख महासागरीय अभियान पर रवाना हुआ है?

- A) Lokayan 26 / लोकायन 26
- B) Samudra Setu / समुद्र सेतु
- C) Sagarmala 25 / सागरमाला 25
- D) Varuna Abhiyan / वरुण अभियान
- E) Ocean Reach / ओशन रीच

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- The Indian Navy's Sail Training Ship INS Sudarshini has embarked on the flagship voyage of Lokayan 26, a 10-month transoceanic expedition.
- भारतीय नौसेना का नौकायन प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शिनी 10 महीने के महासागरीय अभियान 'लोकायन 26' पर रवाना हुआ है।
- The expedition was flagged off from the Naval Base in Kochi.
- इस अभियान को कोच्चि स्थित नौसैनिक अड्डे से रवाना किया गया।
- Reflecting India's maritime heritage and the vision of Vasudhaiva Kutumbakam, the ship will sail over 22,000 nautical miles, visiting 18 foreign ports across 13 countries.
- भारत की समुद्री विरासत और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना को दर्शाते हुए यह पोत 22,000 से अधिक समुद्री मील की यात्रा करेगा और 13 देशों के 18 विदेशी बंदरगाहों पर जाएगा।
- INS Sudarshini is the second sail training ship of the Indian Navy and has already covered more than 1,40,000 nautical miles.
- INS सुदर्शिनी भारतीय नौसेना का दूसरा नौकायन प्रशिक्षण पोत है और अब तक 1,40,000 से अधिक समुद्री मील की यात्रा कर चुका है।
- During this voyage, the ship will represent India at major global maritime events such as Escale à Sète (France) in March–April 2026 and SAIL 250 (USA) in July 2026, including participation in the International Parade of Sails in New York.
- इस यात्रा के दौरान यह पोत मार्च–अप्रैल 2026 में फ्रांस के Escale à Sète और जुलाई 2026 में अमेरिका के SAIL 250 जैसे प्रमुख वैश्विक समुद्री आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, जिसमें न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल परेड ऑफ सेल्स भी शामिल है।

